

सम्पूर्ण-संक्षिप्त-समर्थ

CURRENT AFFAIRS गुरु

UPSC/State PSC परीक्षा की तैयारी करने वाले हिंदी माध्यम के छात्रों के लिए



6th September 2022



FOR DAILY FREE CURRENT AFFAIRS
Follow Our Youtube Channel

 Guru Deekshaa Hindi



INDEX

DAILY CURRENT AFFAIRS NOTES

6th September 2022

1. - राष्ट्रीय जांच एजेंसी के बारे में:.....	3
(i) एनआईए का उद्देश्य है:.....	3
(ii) एनआईए की मांग.....	3
(iii) एनआईए का मिशन:.....	3
(iv) तस्करी और आतंकवादी वित्त पोषण:.....	4
(v) वर्तमान परिवर्तन:.....	4
(vi) एनआईए की शक्ति:.....	4
(vii) विशेष न्यायालय:.....	4
(viii) विशेष न्यायालयों का प्राधिकरण:.....	5
(ix) नए संशोधनों में समस्याएं हैं:.....	5
2. - शहरी सहकारी बैंकों का विवरण:.....	6
(i) सहकारी बैंक क्या हैं?.....	6
(ii) सहकारी बैंक की विशेषताएं:.....	6
(iii) शहरी सहकारी बैंक (यूसीबी) क्या हैं?.....	6
3. - भारतीय मौसम विभाग के बारे में:.....	7
(i) भारतीय मौसम विभाग की पृष्ठभूमि:.....	7
(ii) आईएमडी के लक्ष्य हैं:.....	7
4. - ई-वे बिलों का विवरण.....	8
(i) के बारे में:.....	8
(ii) ई-वे बिल नियम:.....	8



(iii) वैधता:	8
(iv) वैध ई-वे बिल के बिना माल परिवहन के लिए जुर्माना:.....	8

संपादकीय विश्लेषण.....9

1. एनईपी:.....9

(i) नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में क्या शामिल है:	9
(ii) महत्वपूर्ण एनईपी क्लॉज में शामिल हैं:	9
(iii) राष्ट्रीय शिक्षा नीति में निम्नलिखित कठिनाइयाँ हैं:.....	10
(iv) राष्ट्रीय शिक्षा नीति में विशेष रूप से निम्नलिखित क्षेत्रों में सुधार करना होगा:.....	10

2. धान उत्पादन:12

(i) भारत में चावल उगाने के लिए किन विधियों का उपयोग किया जाता है?	12
(ii) निम्नलिखित समूह भारत में विभिन्न प्रकार के चावल का सबसे अच्छा योग करते हैं:.....	12
(iii) भारत के चावल की खेती अनुसंधान और विकास में क्या प्रगति हुई है?.....	13
(iv) चावल उत्पादकों को किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है?.....	13
(v) सीधी धान बोने की तकनीक में क्या शामिल है?.....	14
(vi) निम्नलिखित चरणों को डीएसआर दृष्टिकोण में शामिल किया गया है:	14
(vii) शाकनाशी दो प्रकार के होते हैं:.....	15
(viii) यह क्या लाभ प्रदान करता है?	15
(ix) इसमें क्या खामियाँ हैं?	15
(x) अगला, क्या हमें करना चाहिए?.....	16
(xi) चावल उगाने के लिए कौन सी अतिरिक्त टिकाऊ तकनीकें हैं?	18
(xii) निष्कर्ष:.....	18



1. - राष्ट्रीय जांच एजेंसी के बारे में:

एनआईए की मांग

GS II

विषय→सांविधिक और गैर सांविधिक निकाय

एनआईए का उद्देश्य है:

- नवीनतम खोजी वैज्ञानिक पद्धतियों का उपयोग करते हुए अनुसूचित अपराधों में पूर्ण, सक्षम और गहन जांच करना।
- कानून और भारतीय संविधान को कायम रखना।
- मानव अधिकारों की रक्षा करना और प्रत्येक व्यक्ति की गरिमा को बनाए रखना महत्वपूर्ण है।
- निरंतर प्रशिक्षण और नवीनतम प्रक्रियाओं और प्रथाओं के संपर्क के माध्यम से एक कुशल कर्मचारी की स्थापना करना।
- एक त्वरित और उत्पादक परीक्षण की गारंटी।
- एनआईए अधिनियम के विधायी दायित्वों के अनुपालन में राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और अन्य कानून प्रवर्तन संगठनों की सरकारों के साथ विनम्र और पेशेवर बातचीत बनाए रखना।
- आतंकवादी मामलों की जांच में सभी राज्यों और अन्य जांच एजेंसियों की सहायता करना।
- सरकार और अन्य संगठनों को उपलब्ध आतंकवादियों से संबंधित सभी डेटा का एक डेटाबेस बनाएं।
- आतंकवाद के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय कानून पर शोध और विश्लेषण करें। नियमित रूप से भारतीय कानून की प्रयोज्यता का मूल्यांकन करें। आवश्यकतानुसार परिवर्तन करें।

- मादक पदार्थों, बंदूकों, नकली भारतीय मुद्रा और अन्य संगठित अपराध गतिविधियों की तस्करी की खोज के माध्यम से आतंकवादी घटनाओं के बीच जटिल अंतर-राज्य और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का पता चलता है।
- मुंबई में 2008 के आतंकवादी हमलों के बाद आतंकवाद और अन्य अधिनियमों से संबंधित अपराधों की जांच के लिए एक केंद्रीय संगठन बनाया गया था।

एनआईए का मिशन:

- एनआईए अधिनियम, 2008 की धारा VI के अनुपालन में केंद्र सरकार द्वारा मामलों को एनआईए को हस्तांतरित किया जाता है।
- प्रत्येक मामला एजेंसी द्वारा एक स्वतंत्र जांच के अधीन है।
- एक जांच के बाद, मामलों को बाद में एनआईए विशेष अदालत के समक्ष लाया जाता है।
- गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम 1967 (यूएपीए) और कुछ अन्य कथित अपराध कानूनी आधार हैं, जिस पर एजेंसी केंद्र सरकार से प्रतिवादी पर मुकदमा चलाने के लिए प्राधिकरण के लिए कहती है।
- "प्राधिकरण" यूएपीए की धारा 45 (2) के अनुसार बनाया गया था, और इसकी रिपोर्ट ने निंदा की नींव के रूप में कार्य किया।
- सरकारों की अनुमति के बिना, यह आतंकवाद से संबंधित अपराधों को हर जगह संबोधित करने की शक्ति रखता है।



तस्करी और आतंकवादी वित्त पोषण:

- आतंकवाद की अवधि के भीतर उच्च गुणवत्ता वाले नकली भारतीय मुद्रा तस्करी अपराधों को शामिल करने के लिए एनआईए अधिनियम में संशोधन किया गया है।
- आतंकवाद के वित्तपोषण के कई पहलुओं से निपटने के लिए एनआईए ने एक टेरर फंडिंग एंड फेक करेंसी सेल (टीएफएफसी) बनाया है।
- अपने डेटाबेस में, सेल धोखाधड़ी वाले भारतीय रुपये के नोटों और आतंकवाद के लिए धन (FICN) के मामलों का ट्रैक रखता है।
- जब एनआईए नियमित अपराधों की जांच करती है, तो टीएफएफसी उन मामलों के आतंकवादी पहलुओं के वित्तपोषण को भी देखता है।
- टीएफएफसी सेल नक्सली संगठनों से जुड़े लोगों के बैंक खातों की जांच करता है।
- नक्सली संगठनों द्वारा आतंकवाद के वित्तपोषण से संबंधित मामलों को संभालने के लिए एक विशेष वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) टीम है।
- गृह मंत्रालय एनआईए की सुविधाओं, वित्त पोषण और कर्मियों की आवश्यकताओं की नियमित आधार पर समीक्षा करता है (एमएचए)।

वर्तमान परिवर्तन:

- एनआईए (संशोधन) विधेयक, 2019, जो 2008 के मूल अधिनियम में संशोधन करता है, को संसद द्वारा अपनाया गया था।
- विधेयक का उद्देश्य एनआईए को नीचे निर्दिष्ट नए अपराधों की जांच करने की क्षमता प्रदान करना है:
- नकली धन या बैंक नोट, अवैध हथियार का निर्माण या बिक्री, और मानव तस्करी से जुड़े अपराध

- 1908 के विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के तहत साइबर आतंकवाद और अपराध

एनआईए की शक्ति:

- जब इन अपराधों की जांच की बात आती है तो भारत में एनआईए कर्मचारियों के पास सामान्य पुलिस अधिकारियों के समान अधिकार होते हैं।
- एनआईए के कर्मियों के पास अंतरराष्ट्रीय समझौतों और अन्य देशों के राष्ट्रीय कानूनों के अनुपालन में भारत के बाहर किए गए अनुसूचित अपराधों की जांच करने की शक्ति होगी।
- केंद्र सरकार इन मामलों की जांच के लिए एनआईए को निर्देश दे सकती थी जैसे कि भारत में अपराध किया गया हो।
- इन मुद्दों पर नई दिल्ली की विशेष अदालत का अधिकार क्षेत्र होगा।

विशेष न्यायालय:

- केंद्र सरकार एनआईए अधिनियम 2008 की धारा 11 और 22 के अनुसार अनुसूचित अपराधों के परीक्षण के लिए एक या अधिक विशेष न्यायालयों की स्थापना करती है।
- विशेष न्यायालय की अध्यक्षता एक न्यायाधीश करेगा जिसे उच्च न्यायालय की सिफारिश के मुख्य न्यायाधीश के आधार पर केंद्र सरकार द्वारा चुना जाएगा।
- केंद्र सरकार, यदि आवश्यक हो, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सिफारिश पर विशेष न्यायालय में एक या अधिक अतिरिक्त न्यायाधीशों की नियुक्ति कर सकती है।



विशेष न्यायालयों का प्राधिकरण:

- 1973 की दंड प्रक्रिया संहिता के अनुसार, विशेष न्यायालयों के पास सत्र न्यायालय के समान अधिकार हैं।
- जब भी किसी विशेष न्यायालय की वैधता के संबंध में कोई प्रश्न हो, तो उसे केंद्र सरकार के ध्यान में लाया जाना चाहिए क्योंकि उसका निर्णय अंतिम होता है।
- सर्वोच्च न्यायालय किसी विशेष न्यायालय के समक्ष लंबित किसी मामले को उस राज्य या किसी अन्य राज्य के भीतर किसी अन्य विशेष न्यायालय में कुछ असाधारण परिस्थितियों में स्थानांतरित कर सकता है जहां एक शांत, निष्पक्ष, निष्पक्ष और त्वरित सुनवाई करना संभव नहीं है।
- उसी तरह, उच्च न्यायालय के पास एक सक्रिय मामले को एक राज्य के विशेष न्यायालय से दूसरे राज्य के विशेष न्यायालय में स्थानांतरित करने की शक्ति है।

नए संशोधनों में समस्याएं हैं:

- संविधान की अनुसूची VII के तहत, सार्वजनिक व्यवस्था और पुलिस को बनाए रखना राज्य सूची का मामला है।
- यद्यपि राष्ट्रीय सुरक्षा संघ के क्षेत्राधिकार में शामिल है, आपराधिक कानून समवर्ती सूची में शामिल है।
- केंद्र सरकार ने एनआईए को मानव तस्करी के आरोपों, विस्फोटक अधिनियम के उल्लंघन और शस्त्र अधिनियम के विशेष उल्लंघन जैसे अपराधों की जांच का निर्देश देने का अधिकार दिया है।
- हालांकि, उपरोक्त अधिनियम द्वारा कवर किए गए सभी आपराधिक अपराध देश की सुरक्षा या संप्रभुता के लिए खतरा नहीं हैं, इसलिए देश उनसे निपटने में सक्षम हैं।

- संशोधन विधेयक में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66F को अपराध बताते हुए अनुसूची में शामिल किया गया है।
- धारा 66F साइबर आतंकवाद को कवर करती है।
- हालांकि, भारत में न तो साइबर आतंकवाद की अवधारणा है और न ही डेटा सुरक्षा नियमों का एक सेट मौजूद है।
- एनआईए अधिनियम में संशोधन के कारण अब एनआईए के लिए भारतीय नागरिकों या "भारत के हित को प्रभावित करने वाले" के खिलाफ अपराधों की जांच करना संभव है।
- वाक्यांश "भारत के हितों को प्रभावित करना" अस्पष्ट है, और सरकारें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को सीमित करने के लिए इसका फायदा उठा सकती हैं।
- इसके अलावा, एनआईए को जांच करने का अधिकार देने वाले नियम स्पष्ट रूप से "भारत के हित को प्रभावित करने वाले" को अपराध के रूप में निर्दिष्ट नहीं करते हैं।

• स्रोत→ इंडियन एक्सप्रेस



2. - शहरी सहकारी बैंकों का विवरण:

GS III

विषय→भारतीय अर्थव्यवस्था

सहकारी बैंक क्या हैं?

- यह एक ऐसा व्यवसाय है जिसे विशिष्ट बैंकिंग कार्यों के प्रबंधन के लिए सहकारी आधार पर स्थापित किया गया था। अन्य बैंकों की तरह, सहकारी बैंक भी शेयरों की बिक्री, जमा स्वीकार करने और ऋणों के वितरण के माध्यम से पूंजी जुटाने से शुरू होते हैं।
- वे सहकारी क्रेडिट यूनियन हैं जहां एक ही पड़ोस के सदस्य एक दूसरे को लाभकारी शर्तों पर उधार देने के लिए एक साथ आते हैं।
- वे संबंधित राज्य के सहकारी समिति अधिनियम या 2002 के बहु-राज्य सहकारी समिति अधिनियम के अनुसार पंजीकृत हैं।
- सहकारी बैंक क्रमशः 1949 के बैंकिंग विनियमन अधिनियम और 1955 के बैंकिंग कानून (सहकारी समितियां) अधिनियम द्वारा शासित होते हैं।
- उनमें से ज्यादातर शहरी और ग्रामीण दोनों जगहों पर सहकारी बैंक हैं।

सहकारी बैंक की विशेषताएं:

- सहकारी बैंकों का स्वामित्व और संचालन उनके सदस्यों द्वारा किया जाता है, जो इसके ग्राहक भी हैं। इन संस्थानों के निदेशक मंडल को लोकतांत्रिक रूप से उन सदस्यों द्वारा चुना जाता है, जो बोर्ड के मालिक और शासन करते हैं।
- लाभ आवंटन: सहकारी के वार्षिक लाभ, लाभ, या अधिशेष का कितना हिस्सा उसके सदस्यों को वितरित

किया जा सकता है, इस पर वैधानिक और नियामक सीमाएं हो सकती हैं। इस लाभ का एक बड़ा प्रतिशत अक्सर भंडार के रूप में अलग रखा जाता है।

- वित्तीय समावेशन: उन्होंने बिना बैंक खातों वाले ग्रामीण लोगों को वित्तीय रूप से शामिल होने में काफी सहायता की है। वे ग्रामीण क्षेत्रों में आम जनता को कम लागत वाला वित्त प्रदान करते हैं।

शहरी सहकारी बैंक (यूसीबी) क्या हैं?

- यद्यपि यह शब्द औपचारिक रूप से परिभाषित नहीं है, शहरी सहकारी बैंक (यूसीबी) प्रमुख सहकारी बैंक हैं जो शहरी और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में स्थित हैं।
- शहरी सहकारी बैंक (यूसीबी), प्राथमिक कृषि ऋण समितियां (पीएसीएस), भौगोलिक ग्रामीण बैंक (आरआरबी), और स्थानीय क्षेत्र बैंक (एलएबी) सभी अपनी क्षेत्रीय एकाग्रता के कारण विभेदित बैंकों की श्रेणी में आ सकते हैं।
- 1996 तक, ये बैंक केवल गैर-कृषि उद्देश्यों के लिए ही पैसा उधार दे सकते थे। यह भेद अब प्रासंगिक नहीं है।
- इन बैंकों ने ऐतिहासिक रूप से पड़ोस और पड़ोस-आधारित कार्यसमूहों को प्राथमिकता दी क्योंकि वे बड़े पैमाने पर छोटे उधारकर्ताओं और व्यवसायों को वित्तपोषण प्रदान करते थे। हाल ही में, उनकी परिचालन सीमा बहुत बढ़ गई है।

- स्रोत→ हिन्दू



3. - भारतीय मौसम विभाग के बारे में:

GS II

विषय→सांविधिक और गैर-सांविधिक निकाय

भारतीय मौसम विभाग की पृष्ठभूमि:

- आईएमडी, जिसे आमतौर पर भारत मौसम विज्ञान विभाग के रूप में जाना जाता है, की स्थापना 1875 में हुई थी। मौसम विज्ञान और संबंधित विषयों से संबंधित सभी क्षेत्रों के लिए प्रमुख सरकारी एजेंसी, यह देश की राष्ट्रीय मौसम विज्ञान सेवा के रूप में कार्य करती है।
- भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) की स्थापना 1875 में हुई थी। यह भारत सरकार के पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय का एक प्रभाग है।
- यह मौसम संबंधी अवलोकन, भूकंप विज्ञान और मौसम पूर्वानुमान के प्रभारी प्रमुख एजेंसी है।
- आईएमडी उन छह क्षेत्रीय रूप से केंद्रित मौसम विज्ञान केंद्रों में से एक है जो विश्व मौसम विज्ञान संगठन बनाते हैं।
- नई दिल्ली में उष्णकटिबंधीय चक्रवातों का क्षेत्रीय विशिष्ट मौसम विज्ञान केंद्र (RSMC) उत्तरी हिंद महासागर में चक्रवातों के नामकरण के लिए जिम्मेदार है।
- IMD का मुख्यालय नई दिल्ली में है।

आईएमडी के लक्ष्य हैं:

- कृषि, सिंचाई, नौवहन, विमानन और अपतटीय तेल अन्वेषण जैसे मौसम-संवेदनशील उद्योगों की मदद करने

के लिए मौसम संबंधी डेटा एकत्र करना और वर्तमान और पूर्वानुमान मौसम संबंधी जानकारी प्रदान करना, यथासंभव कुशलता से संचालित करना।

- खतरनाक मौसम की घटनाओं, जैसे उष्णकटिबंधीय चक्रवात, नॉरईस्टर, धूल भरी आंधी, भारी बारिश, बर्फ, ठंड और गर्मी की लहरें, जो संपत्ति की क्षति और मानव मृत्यु दोनों का कारण बन सकती हैं, से संबंधित अलर्ट देने के लिए।
- जल संसाधन, उद्योग, तेल की खोज और अन्य राष्ट्र-निर्माण पहलों के प्रबंधन के लिए आवश्यक मौसम संबंधी जानकारी प्रदान करने के लिए, आईएमडी आवश्यक है।
- संचालन और आगे मौसम विज्ञान और संबंधित विषयों का अध्ययन करने के लिए।

• स्रोत→ हिन्दू



4. - ई-वे बिलों का विवरण

प्रीलिम्स विशिष्ट विषय

के बारे में:

- उत्पादों की आवाजाही शुरू होने से पहले, इसे करने वाला व्यक्ति उचित डेटा अपलोड करता है, और अनुपालन तंत्र के रूप में, जीएसटी पोर्टल पर ई-वे बिल बनाने के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक इंटरफ़ेस का उपयोग करता है।
- एक इलेक्ट्रॉनिक वे बिल, या "ई-वे बिल" प्रणाली का उपयोग उत्पाद और सेवा कर (जीएसटी) शासन में 10 से अधिक लेनदेन के लिए 50,000 रुपये से अधिक मूल्य के उत्पादों के अंतर-राज्य और अंतर-राज्य हस्तांतरण को ट्रैक करने के लिए किया जाता है। किलोमीटर।
- जब एक ई-वे बिल जनरेट होता है, तो एक अद्वितीय ई-वे बिल नंबर (ईबीएन) असाइन किया जाता है और प्रदाता, प्राप्तकर्ता और ट्रांसपोर्टर को उपलब्ध कराया जाता है।
- इसे अधिक तेजी से उत्पाद रोटेशन को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया था।
- वाहनों के लिए टर्नअराउंड समय कम करें।
- औसत यात्रा दूरी बढ़ाएं, लागत और यात्रा के समय को कम करें, और रसद उद्योग की सहायता करें।

ई-वे बिल नियम:

- उल्लिखित ई-वे बिल मानदंड निर्दिष्ट करते हैं कि उत्पादों को स्थानांतरित करने के लिए, प्रत्येक प्रदाता को पहले ई-वे बिल पोर्टल पर ऑनलाइन पंजीकरण करना होगा।

- कर से बचने के लिए, कर अधिकारियों को ई-वे बिल की समीक्षा करने का अधिकार है, जबकि यह चल रहा है।

वैधता:

- विनियमों के अनुसार, पारंपरिक कार्गो (अति-आयामी माल ढुलाई के अलावा) के लिए परमिट केवल एक दिन की यात्रा के लिए 100 किमी की दूरी पर और उसके बाद के दिनों के लिए उसी अनुपात में मान्य होते हैं।
- सिद्धांत रूप में, ई-वे बिल की वैधता को बढ़ाया नहीं जा सकता है; फिर भी, एक आयुक्त सीमित संख्या में मदों के लिए अधिसूचना भेजकर ही ऐसा कर सकता है।

वैध ई-वे बिल के बिना माल परिवहन के लिए जुर्माना:

- 10,000 रुपये का जुर्माना या कर की राशि जिसे चोरी करने का प्रयास किया जा रहा है, जो भी अधिक हो, कर अधिकारियों द्वारा लगाया जा सकता है।
- ऐसे में माल और उन्हें ले जाने वाले वाहन को सीज या इंपाउंड किया जा सकता है।
- ई-वे बिल की समय सीमा समाप्त होने से पहले ट्रांसपोर्टर द्वारा उसका नवीनीकरण किया जा सकता है; हालाँकि, यदि ई-वे बिल पहले ही समाप्त हो चुका है, तो सिस्टम उसी चालान से जुड़े पुनर्जनन को प्रतिबंधित करता है।

स्रोत→ हिन्दू



संपादकीय विश्लेषण

1. एनईपी:

नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में क्या शामिल है:

- एनईपी कस्तूरीरंगन और टीएसआर सुब्रमण्यम समितियों के सुझावों पर बनाया गया था। एनईपी, 2020 बचपन से ही उच्च शिक्षा के माध्यम से शिक्षा में सुधार को उच्च प्राथमिकता देता है। इसका उद्देश्य भारत की शिक्षा प्रणाली को बढ़ाना है ताकि यह समकालीन अपेक्षाओं को बेहतर ढंग से पूरा कर सके।

महत्वपूर्ण एनईपी क्लॉज में शामिल हैं:

कक्षाओं में सीखना:

- वर्ष 2030 तक माध्यमिक विद्यालय के माध्यम से प्रारंभिक बचपन से 100 प्रतिशत के जीईआर (सकल नामांकन अनुपात) तक पहुंचना
- उन बच्चों के लिए एक खुली शिक्षा प्रणाली उपलब्ध है जो स्कूल में नहीं हैं (एनआईओएस जैसे प्रवेश मानकों के बिना)।
- वर्तमान 10+2 प्रणाली को 5+3+3+4 पाठ्यक्रम ढांचे से बदल दिया जाएगा।
- मातृभाषा प्रशिक्षण केवल कक्षा 5 तक आवश्यक है।

उच्च शिक्षा:

- क्षेत्रीय भाषा स्नातक कार्यक्रम भी पेश किए जाते हैं। एक लचीला पाठ्यक्रम, व्यावसायिक शिक्षा का एकीकरण,

और प्रासंगिक डिग्री के साथ विभिन्न प्रवेश और निकास बिंदु यूजी (स्नातक) शिक्षा की सभी विशेषताएं हैं, जो व्यापक-आधारित, बहु-विषयक और समग्र है।

- कानूनी और चिकित्सा शिक्षा के अपवाद के साथ संस्थानों के बीच क्रेडिट हस्तांतरण को आसान बनाने के लिए क्रेडिट के अकादमिक बैंक, एचईसीआई (भारत का उच्च शिक्षा आयोग) शैक्षणिक संस्थानों में बहुभाषावाद को बढ़ावा देने के लिए छात्रा नियामक के रूप में

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार निम्नलिखित परिवर्तन किए गए हैं:

- राष्ट्रीय बोर्डों ने कोविड वर्ष के दौरान भलाई, समावेशी शिक्षा, आनंदमय शिक्षा आदि से जुड़ी कक्षा की गतिविधियों में कई बदलाव करने का प्रयास किया।
- सीबीएसई अपने परिचालन सहोदय स्कूल परिसरों के माध्यम से निष्पादन की निगरानी के लिए एक कार्य समूह के साथ एनईपी कार्यक्रमों का नेतृत्व करने के लिए प्रशिक्षण मॉड्यूल बनाने के लिए काम कर रहा है।
- अभी लर्निंग हब चल रहे हैं। जहां शिक्षक डिजाइन सोच, आविष्कार आदि में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं, वहां परामर्श क्षमता बढ़ाने के लिए नवाचार राजदूत कार्यक्रम विकसित किए जा रहे हैं। परिणामस्वरूप, भविष्य के स्कूलों को और अधिक मजबूती और समझदारी से डिजाइन किया जाएगा।
- राष्ट्रीय शिक्षा नीति में निम्नलिखित पहलों को ध्यान में रखा गया है:
- नीति की पहली वर्षगांठ पर, केंद्र ने एनईपी (राष्ट्रीय शिक्षा नीति) की कुछ घोषित परियोजनाओं को सार्वजनिक रूप से शुरू करने का निर्णय लिया।



यह भी शामिल है:

- 290 से अधिक शीर्ष विश्वविद्यालयों के छात्र वर्तमान शैक्षणिक वर्ष 2021-2022 में शुरू होने वाले बहुप्रतीक्षित एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट का उपयोग कर सकेंगे।
- राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग ढांचे के शीर्ष 100 में संस्थान और राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद से ए रेटिंग वाले संस्थान दोनों ही क्रेडिट ट्रांसफर सिस्टम में भाग लेने के लिए योग्य हैं।
- अकादमिक बैंक ऑफ क्रेडिट द्वारा प्रत्येक छात्र के अकादमिक क्रेडिट को फाइल पर रखा जाएगा। यह विश्वविद्यालयों से केवल क्रेडिट पाठ्यक्रमों के लिए कागजी कार्रवाई स्वीकार करेगा, जिसमें छात्रों के खातों में पैसा डालना होगा। छात्रों की पाठ्यक्रम सामग्री को उनके द्वारा किए जा रहे किसी भी पाठ्यक्रम के लिए क्रेडिट के लिए तुरंत नहीं लिया जाएगा।
- इससे छात्रों के लिए अपने क्रेडिट को सत्यापित करना, क्रेडिट बनाना, क्रेडिट ट्रांसफर करना और रिडीम करना और पदोन्नत होना आसान हो जाएगा।
- सरकार जल्द ही घोषणा करेगी कि लगभग 14 छोटे विश्वविद्यालय स्थानीय भाषाओं में इंजीनियरिंग की डिग्री प्रदान करना शुरू कर देंगे।
- सरकार राष्ट्रीय शिक्षा प्रौद्योगिकी मंच और राष्ट्रीय डिजिटल शिक्षा वास्तुकला पेश करेगी।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति में निम्नलिखित कठिनाइयाँ हैं:

- भारत में वर्तमान में महत्वपूर्ण सीखने की कमी है। ऐसा इसलिए है क्योंकि बच्चों की ज़रूरतें अधिक विशिष्ट होती हैं और उन्हें केवल ऑनलाइन ही संतुष्ट नहीं किया जा सकता है। स्कूल बंद होने और वायरस के डर के कारण

बच्चे अपने ज्ञान, समझ, पढ़ने और बोलने के कौशल से संपर्क खो रहे हैं।

- डिजिटल डिवाइड ने भारत में शिक्षा के अंतर में योगदान दिया है। आज, 90% से अधिक भारतीय छात्रों के पास ऑनलाइन सीखने में पूरी तरह से भाग लेने के लिए आवश्यक तकनीकों तक पहुंच नहीं है।
- भले ही सरकार अधिक स्वायत्तता की वकालत करती है, फिर भी कई विश्वविद्यालय पूर्णकालिक प्रमुखों और कुलपतियों के बिना कार्य करते हैं। उदाहरण के लिए, दिल्ली विश्वविद्यालय और जेएनयू जैसे दस महत्वपूर्ण विश्वविद्यालयों से पूर्णकालिक प्रशासक अनुपस्थित हैं।
- यद्यपि सरकार ने स्कूली शिक्षा के लिए लगभग 5,000 करोड़ रुपये और उच्च शिक्षा के लिए 1,000 करोड़ रुपये की कटौती की है, एनईपी साक्षरता और संख्यात्मकता को सर्वोच्च प्राथमिकता देने का आह्वान करता है।
- बारहवीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाओं को रद्द करने के परिणामस्वरूप उच्च शिक्षा संस्थानों को जिन चुनौतियों का सामना करना पड़ा, उन पर विचार करना भी महत्वपूर्ण है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति में विशेष रूप से निम्नलिखित क्षेत्रों में सुधार करना होगा:

- हितधारकों को उत्साहित करने और एनईपी को आगे बढ़ाने के लिए, भारत को एक मजबूत संस्थागत ढांचे और पर्याप्त क्षमता निर्माण की आवश्यकता है। प्रत्येक हितधारक को एनईपी के लिए समर्पित होना चाहिए और राज्य, जिला, उप-जिला और ब्लॉक स्तर पर इसकी अवधारणाओं को समझना चाहिए।
- यह सुनिश्चित करने के लिए शिक्षा निदेशालयों में सुधार किया जाना चाहिए कि यह नीति जिला और क्षेत्रीय स्तर के शैक्षिक समूहों में व्याप्त हो।



- बच्चों को उनकी पूरी क्षमता हासिल करने में सक्षम बनाने के लिए, भारत को प्रभावी रणनीतियां अपनानी चाहिए जो कंप्यूटर और अन्य प्रौद्योगिकी तक पहुंच में सुधार करें, शिक्षकों और छात्रों के लिए बेहतर उपकरणों के साथ कक्षाओं को लैस करें, इंटरैक्टिव व्हाइटबोर्ड स्थापित करें, और तेज़, भरोसेमंद इंटरनेट कनेक्टिविटी की गारंटी दें।
- भारत को वयस्कों और बच्चों दोनों के टीकाकरण को प्राथमिकता देनी होगी क्योंकि ऐसा करने से स्कूलों को फिर से खोलने में तेजी आएगी।
- राष्ट्रीय राज्य और राष्ट्रीय संगठनों को पायलट परियोजनाओं के साथ शुरू करना चाहिए। मास्टर प्रशिक्षकों का होना आवश्यक है जो शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में स्कूल प्रशासकों और शिक्षकों को निर्देश दे सकें।
- आवश्यक वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराना:
- यह सुनिश्चित करने के लिए कि एनईपी फंड उपलब्ध हैं और कार्यान्वयन प्रक्रिया में देरी न हो, एक विशेष प्रयोजन वाहन (एसपीवी) स्थापित किया जाना चाहिए।
- भारत को सार्वजनिक और निजी दोनों उच्च शिक्षा संस्थानों को वित्तपोषित करने के लिए निजी परोपकार को बढ़ावा देना चाहिए।
- मौजूदा कर प्रोत्साहनों के साथ, नए और अतिरिक्त लोगों को पेश किया जाना चाहिए।



2. धान उत्पादन:

भारत में चावल उगाने के लिए किन विधियों का उपयोग किया जाता है?

- चावल की उत्पत्ति के संबंध में कई मत हैं। दूसरों का मानना है कि यह दक्षिणी भारत में उत्पन्न हुआ और हिमालय की तलहटी से चीन, कोरिया, फिलीपींस, जापान आदि देशों में फैल गया।
- दो शुरुआती प्रकार के घरेलू चावल हैं इंडिका, जो पूर्वी हिमालय की तलहटी से आता है, और जपोनिका (दक्षिणी चीन में उत्पन्न)।
- भारत प्रमुख चावल उत्पादकों में से एक है। यह बासमती का प्रमुख निर्यातक है।
- भारत में अद्वितीय चावल की किस्मों की खेती की जाती है, जिनमें जैस्मीन, अंबेमोहर (महाराष्ट्र को जीआई-टैग किया गया), सेरागा सांबा, आदि शामिल हैं। मणिपुर का काला चावल जिसे "चाखाओ" के नाम से जाना जाता है, भारतीय चावल की सूची में शामिल होने वाली सबसे हालिया चावल की किस्म है। जीआई टैग वाली किस्में
- पश्चिम बंगाल वह जगह है जहाँ भारत के अधिकांश चावल का उत्पादन होता है। चावल का उत्पादन पंजाब, उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु जैसे राज्यों में भी महत्वपूर्ण है।
- 2011 में सबसे अधिक चावल उत्पादन का एक नया रिकॉर्ड देखा गया जब एक भारतीय किसान ने एक हेक्टेयर से 22 टन चावल काटा।
- भारत में चावल ज्यादातर खरीफ मौसम के दौरान उगाया जाता है, खासकर उत्तरी राज्यों में। हालाँकि, यह पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, ओडिशा और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों में रबी की फसल के रूप में भी उगाया जाता है।

- तमिलनाडु के किसानों ने नौ साल में पहली बार कुरुवई चावल उगाना शुरू किया है। इस सीमित फसल मौसम के दौरान, कावेरी नदी डेल्टा क्षेत्र में चावल की खेती की जाती है।
- फसल कई प्रकार के आवासों में हाइड्रोलॉजिकल, जलवायु और मिट्टी की स्थितियों के साथ बढ़ने में सक्षम है। इसकी खेती सिंचित भूमि, तराई क्षेत्रों में की जा सकती है जो वर्षा से पानी प्राप्त करते हैं, ज्वारीय दलदल, उच्च भूमि आदि।
- लंबे समय तक धूप और पानी की निरंतर आपूर्ति के साथ गर्म, आर्द्र जलवायु चावल की वृद्धि के लिए आदर्श है। इसके लिए 21 से 37 डिग्री सेल्सियस के बीच औसत तापमान की आवश्यकता होती है।

निम्नलिखित समूह भारत में विभिन्न प्रकार के चावल का सबसे अच्छा योग करते हैं:

- तटीय प्रजातियां
- तराई की नस्लें
- कई कारकों के आधार पर विभिन्न खेती विधियों का उपयोग किया जाता है, जैसे कि मिट्टी के गुण, पानी की उपलब्धता, श्रम शक्ति, जलवायु आदि।
- तराई गीली चावल की खेती के तरीके: पोखर के एक खेत में बीज फैलाना और पोखर वाले खेतों में रोपाई भी विधियाँ हैं।
- कीचड़ वाले क्षेत्रों में रोपाई की प्रथा सबसे अधिक इस्तेमाल की जाने वाली बागवानी विधियों में से एक है। ये शामिल कदम हैं:



- बीज मूल रूप से अंकुरित होते हैं और नर्सरी में देखभाल की जाती है। नर्सरी बेड मुख्य खेत के 15 से 20 प्रतिशत हिस्से पर कब्जा कर लेते हैं, जहां बाद में फसलें उगाई जाएंगी।
- 25 से 35 दिनों के बाद रोपाई को कीचड़ वाले खेत में लगाया जाता है।
- यदि कोई वर्षा नहीं होती है, तो 2 से 5 सेमी पानी की गहराई बनाए रखने के लिए फसलों को पहले तीन हफ्तों के लिए व्यावहारिक रूप से हर दिन पानी पिलाया जाना चाहिए।
- फसल टिलरिंग अवस्था में होती है जब तने के विकास के बाद के 4-5 सप्ताह होते हैं। इस अवधि के दौरान हर दो से तीन दिनों में एक बार फसलों को पानी पिलाया जाता है।
- जुताई के बाद खेत को बाढ़ की आवश्यकता नहीं होती है।
- क्षेत्र में बाढ़ इस सिद्धांत पर आधारित है कि यह खरपतवार के विकास को रोक सकता है, जो अपने प्रारंभिक विकास चरणों के दौरान पोषक तत्वों, प्रकाश और पानी के लिए रोपाई के साथ प्रतिस्पर्धा करता है।
- पानी ऑक्सीजन की आपूर्ति को हटाकर खरपतवार के विकास को रोककर एक खरपतवार नाशक के रूप में कार्य करता है। चावल की पौध पर इसका बहुत कम प्रभाव पड़ता है क्योंकि उनके पास एरेन्काइमा होता है, एक नरम ऊतक जो ऑक्सीजन को जड़ों के माध्यम से प्रवेश करने की अनुमति देता है।

भारत के चावल की खेती अनुसंधान और विकास में क्या प्रगति हुई है?

- भारत ने 1911 से चावल का प्रजनन शुरू कर दिया है। चावल पर अधिक गहन शोध 1920 में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR) की स्थापना के बाद शुरू हुआ।

- 1946 में, चावल अनुसंधान के क्षेत्र को आगे बढ़ाते हुए, केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान की स्थापना की गई।
- भारत में चावल का उत्पादन, उत्पादकता और लाभप्रदता बढ़ाने के लिए, ICAR ने 1965 में अखिल भारतीय समन्वित चावल सुधार परियोजना (AICRIP) शुरू की।
- AICRIP कार्यक्रम के तहत सबसे महत्वपूर्ण चावल प्रजनन पहलों में से एक ताइचुंग (मूल) -I का विकास था। प्रकट होने वाले शुरुआती AICRIP प्रकारों में से दो पद्म और जया थे।
- भारत में 1,200 से अधिक विभिन्न चावल की किस्में पाई जा सकती हैं।

चावल उत्पादकों को किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है?

- नाबार्ड की 2018 की जल उत्पादकता रिपोर्ट के अनुसार, चावल भारत की सबसे अधिक पानी की खपत वाली फसलों में से एक है।
- सीमित जल आपूर्ति वाले स्थानों में, धान पर अधिक निर्भरता से भूजल पर दबाव पड़ेगा। हरियाणा राज्य को ही लें, जो अपनी पीने के पानी की 95% और कृषि की 61% जरूरतों के लिए भूजल पर निर्भर है। राज्य में भूजल निकासी को अत्यधिक दोहन दिखाया गया है।
- चावल की खेती अक्सर श्रम-गहन विधियों का उपयोग करके की जाती है, जिसमें बीजों को मैन्युअल रूप से खेतों से अंकुरण अवस्था तक ले जाया जाता है। COVID-19 संघर्ष के लॉकडाउन और बड़े पैमाने पर श्रमिक आंदोलन का अनाज राज्यों में चावल की खेती पर काफी प्रभाव पड़ा।



- ऊर्ध्व और तराई दोनों क्षेत्रों में कृषि क्षेत्र अपर्याप्त मिट्टी की नमी प्रतिधारण के साथ संघर्ष करते हैं। जबकि तराई क्षेत्रों में सूखा एक प्रमुख चिंता का विषय है, वर्षा जल तेजी से ऊपर के स्थानों से निकल जाता है।
- चावल की खेती उन स्थानों में चुनौतीपूर्ण है जहां बाढ़ की संभावना है (असम की तरह), निचले इलाके हैं, और अचानक बाढ़, जलभराव आदि के कारण अपर्याप्त जल निकासी है। इसके अतिरिक्त, खतरनाक टूटने वाले उपोत्पाद और मिट्टी की लोहे की विषाक्तता इन क्षेत्रों में जमा होती है।
- मिट्टी के कटाव के कारण मिट्टी की उर्वरता में कमी। खारापन और भूमि क्षरण अन्य मुद्दे हैं।
- प्रभावी उर्वरक उपयोग की कमी है।
- खेती की तकनीक में कमियां प्रसारण विधि का उपयोग करते समय, सभी बीजों का अंकुरण नहीं होता है, जिसके परिणामस्वरूप फसल पौधों की एक छोटी आबादी होती है। अनिश्चित मानसून के कारण प्रत्यारोपण प्रक्रिया में देरी और अक्षम है।
- चावल की खेती करने वाले समुदाय का लगभग 78 प्रतिशत छोटे और सीमांत बागान मालिक हैं। उनकी आर्थिक निरक्षरता के कारण अधिक आधुनिक फसल उत्पादन प्रथाओं और आवश्यक कृषि आदानों को अपनाने के लिए उनके पास अक्सर संसाधनों की कमी होती है।
- चावल की खेती और जलवायु परिवर्तन जुड़े हुए हैं। ऐसा कहा जाता है कि बाढ़ वाले क्षेत्र अवायवीय परिस्थितियों के कारण मीथेन जैसी ग्रीनहाउस गैसों का उत्पादन करते हैं। ये स्रोत दुनिया के सभी GHG उत्सर्जन का 5% तक हैं।
- जलवायु परिवर्तन चावल की खेती को भी प्रभावित करता है। चरम मौसम का उस पर प्रभाव पड़ता है।

सीधी धान बोने की तकनीक में क्या शामिल है?

- हाल ही में, पंजाब और हरियाणा ने अपने किसानों पर प्रथागत रोपाई दृष्टिकोण से चावल की सीधी सीडिंग, या डीएसआर में संक्रमण के लिए दबाव डाला।
- ट्रैक्टर द्वारा संचालित उपकरणों का उपयोग करके बीजों को सीधे मुख्य क्षेत्र में ड्रिल किया जाता है। नर्सरी या प्रत्यारोपण की कोई आवश्यकता नहीं है।
- प्रथा के अनुसार पानी को एक शाकनाशी के रूप में उपयोग करने के बजाय, डीएसआर तकनीक खरपतवार की समस्या से निपटने के लिए वास्तविक रासायनिक कीटनाशकों का उपयोग करती है।
- डीएसआर के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला ऐसा ही एक उपकरण लकी सीड ड्रिल है, जिसे पंजाब कृषि विश्वविद्यालय द्वारा विकसित किया गया था। यह उपकरण एक साथ कीटनाशकों का छिड़काव कर सकता है और बीज बो सकता है। हैप्पी सीडर के विपरीत, जिसका उपयोग जलती हुई पराली की समस्या से निपटने के लिए किया जाता था, यह अलग है।

निम्नलिखित चरणों को डीएसआर दृष्टिकोण में शामिल किया गया है:

- यह सुनिश्चित करने के लिए कि पानी समान रूप से फैला हुआ है, जमीन को लेजर लेवलर से समतल किया जाता है।
- मिट्टी की नमी के आदर्श स्तर को बनाए रखने के लिए, बुवाई से पहले या "रौनी" से जमीन की सिंचाई की जाती है।
- खेत की सतह को दो बार जुताई और तख्ती से समतल किया जाता है।



- ट्रैक्टर से चलने वाले उपकरण का उपयोग जड़ी-बूटियों को फैलाने और जमीन पर बीज लगाने के लिए किया जाता है।

शाकनाशी दो प्रकार के होते हैं:

- पूर्व-आकस्मिक एजेंट अंकुरण से पहले उपयोग की जाने वाली जड़ी-बूटियों को संदर्भित करते हैं। इस किस्म का उपयोग लकी सीड ड्रिल मशीन द्वारा किया जाता है। इसके अतिरिक्त, सामान्य सीड ड्रिल के साथ बुवाई के तुरंत बाद इसका उपयोग किया जा सकता है। पेंडिमेथालिन के बारे में सोचें।
- बीज बोने के 20-25 दिनों के बाद उभार के बाद हर्बिसाइड्स लगाए जाते हैं। उदाहरण के लिए, बिसपायरीबैक-सोडियम और फेनोक्साप्रोप-पी-एथिल।

यह क्या लाभ प्रदान करता है?

- जल का संरक्षण किया जाता है। यह प्रत्यारोपण रणनीति की तुलना में 30-40% कम पानी का उपयोग करता है।
- बुवाई के 21 दिन बाद ही रौनी के बाद प्रारंभिक सिंचाई की आवश्यकता होती है। इसकी तुलना प्रतिरोपण विधि से करें, जब बाढ़ वाली भूमि को बनाए रखने के लिए लगभग हमेशा सिंचाई की आवश्यकता होती है।
- श्रम खर्च कम हो जाता है। इस लाभ के कारण ही अब अत्यधिक श्रम की कमी की स्थितियों के दौरान इसे प्राथमिकता दी जाती है। हालांकि, पंजाब के खेतों को केवल पोखर दृष्टिकोण का उपयोग करके उन्हें विकसित करने के लिए 600,000 कर्मचारियों की आवश्यकता हो सकती है।
- यह अधिक उचित मूल्य और लागत प्रभावी है। विशेषज्ञ बताते हैं कि सामान्य परिस्थितियों में प्रत्यारोपण के लिए

श्रम लागत लगभग 2,400 रुपये/एकड़ हो सकती है, डीएसआर रणनीति के तहत कीटनाशक व्यय 2,000 रुपये/एकड़ से कम होगा (जो मौजूदा संकट काल में काफी अधिक होगा)।

- यह समय बचाने का एक तरीका है। पोखर तकनीक में, प्रत्यारोपण प्रक्रिया में एक सप्ताह का समय लगता है। डीएसआर के लिए बीज बोने के लिए कुछ दिन काफी होंगे।

इसमें क्या खामियां हैं?

- जड़ी-बूटियों तक पहुंच एक गंभीर समस्या है।
- डीएसआर विधि का उपयोग करते समय अधिक बीजों की आवश्यकता होती है। प्रति एकड़ 4-5 किलो बीज प्रतिरोपण विधि की तुलना में, डीएसआर रणनीति के लिए 8-10 किलोग्राम की आवश्यकता होती है।
- परिणाम प्रदान करने के लिए डीएसआर तकनीक के लिए लेजर लेवलिंग आवश्यक है। इस विधि की लागत 1,000 रुपये प्रति एकड़ है। इस बात की कोई आवश्यकता नहीं है कि प्रत्यारोपण विधि उसी को नियोजित करे।
- मानसून की शुरुआत बुवाई के समय के साथ होनी चाहिए। जून के पहले सप्ताह तक बीज बोना समाप्त हो जाना चाहिए, और मानसून से पहले बीज अंकुरित होना शुरू हो जाना चाहिए। चूंकि पौध पहले नर्सरी में उगाए गए थे, इसलिए रोपाई के समय यह कोई समस्या नहीं है।
- लकी सीड ड्रिल जैसी नई तकनीक को अपनाने से चावल किसानों की अनिश्चित वित्तीय स्थिति के परिणामस्वरूप चुनौतियों का सामना करना पड़ता है।
- किसान आमतौर पर धैर्य खो देते हैं जब 21 दिनों के भीतर बीज पर्याप्त रूप से अंकुरित नहीं होते हैं और सिंचाई की ओर रुख करते हैं, जो प्रक्रिया के परिणामों पर नकारात्मक प्रभाव डालते हैं।



- कुछ विशेषज्ञों ने चिंता व्यक्त की है कि रणनीति के परिणामस्वरूप "कृषि का निगमीकरण" हो सकता है, जो एक चिंता का विषय है।
- कृषि यंत्रीकरण के परिणामस्वरूप किसान ऐतिहासिक रूप से अल्प-रोजगार के शिकार रहे हैं। यह समस्याएँ पैदा कर सकता है यदि और जब कर्मचारी COVID के बाद इन क्षेत्रों में लौटने का निर्णय लेते हैं।
- पर्यावरण पर शाकनाशियों के उपयोग के संभावित प्रभाव भी चिंता का विषय रहे हैं।

अगला, क्या हमें करना चाहिए?

- विश्लेषकों का अनुमान है कि चावल की मांग जल्द ही कम नहीं होगी। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान (IRRI) के अनुसार, प्रत्याशित मांग को पूरा करने के लिए चावल के उत्पादन में अगले दो दशकों में 25% की वृद्धि होनी चाहिए।
- यह अनुमान लगाया गया है कि अनाज रखने वाले राज्यों में किसानों का एक बड़ा हिस्सा फसल की लाभप्रदता के कारण निकट भविष्य में चावल की खेती करता रहेगा। पंजाब में 27 लाख हेक्टेयर में चावल उगाने की योजना है। इनमें से 7 लाख हेक्टेयर का उपयोग बासमती चावल की खेती के लिए किया जाएगा, जो अपनी असाधारण गुणवत्ता के लिए प्रसिद्ध है।
- कई किसान अब डीएसआर तकनीक का उपयोग करते हैं (हालांकि छोटे पैमाने पर), और उन्होंने प्रतिरोपण की तुलना में पैदावार की सूचना दी है। इसलिए विधि को अपनाना काफी सरल होना चाहिए क्योंकि उन्हें केवल अपने अभ्यास में सुधार करने की आवश्यकता है।
- पंजाबी सरकार 2009-2010 से व्यापक रूप से डीएसआर तकनीक को अपनाने को बढ़ावा देने के लिए (सफलता की विभिन्न डिग्री के साथ) प्रयास कर रही है। इस समय

मौजूद श्रम की गंभीर कमी हमें इस लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद करेगी। यहां तक कि प्रारंभिक अनुमानों से संकेत मिलता है कि डीएसआर की खेती के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला क्षेत्र पिछले वर्ष की तुलना में आठ गुना अधिक है।

- इसके अलावा, सरकारें उस लागत को कम कर रही हैं जिस पर डीएसआर उपकरणों की पेशकश की जाती है। यह महत्वपूर्ण है, जैसा कि हरित क्रांति के शुरुआती चरणों के दौरान प्रौद्योगिकी को असमान रूप से अपनाने से देखा जाता है। 1950 और 1960 के दशक से एक सबक यह है कि कृषक समुदाय के सभी क्षेत्रों में नई कृषि प्रौद्योगिकी से लाभों का समान वितरण सुनिश्चित करने में सरकार की भूमिका का महत्व है।
- कई समस्याओं का समाधान भी किसानों ने खुद किया है। उदाहरण के लिए, नई मशीनरी खरीदने से बचने के लिए, कुछ किसानों ने हैप्पी सीडर मशीनों, जो आमतौर पर गेहूं की बुवाई के लिए उपयोग की जाती हैं, को डीएसआर पद्धति का उपयोग करके धान के बीज बोने के लिए परिवर्तित कर दिया है।
- हालांकि, खेतों की सेहत सबसे अच्छी नहीं है। डीएसआर रणनीति में किसानों के विश्वास को ठेस पहुंची है क्योंकि जून की शुरुआत की बारिश के बाद भी शायद ही कई अंकुर निकले हों। पंजाब में बहुत सारे किसान अपने बीज खोने के डर से डीएसआर दृष्टिकोण से प्रत्यारोपण पद्धति में स्थानांतरित हो गए हैं, खासकर उस अवधि के दौरान जब अर्थव्यवस्था कमजोर होती है।
- इसके परिणामस्वरूप किसानों को केवल समय, धन, इनपुट और श्रम के मामले में अधिक नुकसान का अनुभव होगा।



- कृषि अधिकारियों को विधि के बारे में आशंकाओं को दूर करने के लिए पर्याप्त मार्गदर्शन और सहायता प्रदान करनी चाहिए। इसके लिए आप राज्य की कृषि वेबसाइट या कृषि विस्तार एजेंसी के माध्यम से ऑनलाइन सहायता प्राप्त कर सकते हैं।
- अधिक से अधिक किसानों को अधिक आश्वासन के साथ तकनीक को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए अभ्यास के ज्ञान को बढ़ाना और सफलता की कहानियों को उजागर करना महत्वपूर्ण है।
- पंजाब और हरियाणा जैसे अनाज उत्पादक क्षेत्रों में कार्यरत कृषि मजदूरों की एक बड़ी संख्या उत्तर प्रदेश और बिहार से आती है। कृषि के मशीनीकरण से खेतिहर मजदूरों का नुकसान होगा, हालाँकि इसकी भरपाई बड़े पैमाने पर स्थानीय रोजगार के अवसरों के खुलने से होगी।
- जल दक्षता में सुधार के लिए ड्रिप सिंचाई, स्प्रिंकलर सिस्टम और सूक्ष्म सिंचाई का सुझाव दिया जाता है।
- उच्च अश्वशक्ति इंजन का उपयोग करने वाले किसानों के लिए, भूजल आपूर्ति पर बोझ को कम करने के लिए चावल के रोपण को मना किया जा सकता है।
- ऐसे नए क्षेत्रों में चावल लगाना संभव हो सकता है जहां हाल ही में इसकी खेती नहीं की गई है।
- मल्लिंग और गैर-सिंथेटिक शाकनाशी रासायनिक शाकनाशी के उपयोग के दो विकल्प हैं।
- यह देखते हुए कि हरित क्रांति के दौरान खाद्य उत्पादन बढ़ाने के सरकारी उपायों ने ज्यादातर उन क्षेत्रों में चावल की खेती को बढ़ावा दिया, जिन्होंने ऐतिहासिक रूप से फसल नहीं उगाई थी, अब यह फिर से सरकार की जिम्मेदारी है कि वह "रिवर्स / ऊर्ध्वगामी संक्रमण" को प्रोत्साहित करे।
- यह महसूस करना महत्वपूर्ण है कि वहां मौजूद गंभीर पानी की कमी के कारण कई स्थान चावल की खेती के लिए अनुपयुक्त हैं। सरकार को इसे स्वीकार करना चाहिए और विविधीकरण की पहल को लागू करना चाहिए। उदाहरण के लिए, हरियाणा सरकार ने चावल उगाने वाली 1 लाख हेक्टेयर भूमि को अन्य फसल खेती (मक्का की तरह) में बदलने का फैसला किया।
- एक संभावना विविधीकरण को प्रोत्साहित करना है। उदाहरण के लिए, हरियाणा सरकार ने हाल ही में "मेरा पानी- मेरी विरासत" वित्तीय प्रोत्साहन से जुड़े विविधीकरण कार्यक्रम की शुरुआत की, जिसके तहत जो किसान चावल से मक्का, बाजरा, कपास और बागवानी फसलों की ओर पलायन करते हैं, उन्हें 7,000 रुपये / एकड़ का भुगतान किया जाता है।
- एमएसपी की पेशकश करके, चावल और मक्का जैसी अन्य फसलों के बीच लाभ अंतर को बंद किया जा सकता है। कृषक समुदाय का विश्वास जीतने के लिए ऐसी प्रतिबद्धताओं को पूरा करना एक महत्वपूर्ण घटक है।
- सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कुछ चावल को अन्य अनाज जैसे मक्का, बाजरा, और अन्य पारंपरिक अनाज के साथ प्रतिस्थापित करके, विविधीकरण को और अधिक समर्थन दिया जा सकता है। बेहतर स्वास्थ्य को प्रोत्साहित करने और इन प्रतिस्थापनों की मांग उत्पन्न करने के लिए, ऐसे अनाजों को मध्याह्न भोजन योजनाओं और पोषण योजनाओं में भी शामिल किया जा सकता है।



चावल उगाने के लिए कौन सी अतिरिक्त टिकाऊ तकनीकें हैं?

निष्कर्ष:

- खाद्य और कृषि संगठन ने "कम के साथ अधिक उत्पादन" सेव एंड ग्रो तकनीक की शुरुआत की। यह प्रभावी जल प्रबंधन, उपयुक्त फसल विकल्प और संरक्षण कृषि जैसे विषयों पर केंद्रित है।
- चावल और मछली की खेती: इस तकनीक का उपयोग करके चावल के खेतों में पानी भरकर मछलियों को पाला जाता है। मिट्टी के पोषण में सुधार के अलावा, ये मछलियां किसानों को अतिरिक्त राजस्व अर्जित करने और चावल के खेतों से मीथेन उत्सर्जन को कम करने में मदद करती हैं। इससे उर्वरकों और कीटनाशकों की आवश्यकता कम हो जाती है।
- चावल गहनता प्रणाली (एसआरआई) दृष्टिकोण 1980 के दशक में मेडागास्कर में पाया गया था। इस तकनीक से पूरे क्षेत्र में कम बीज समान रूप से वितरित किए जाते हैं। जैविक खाद से खेतों में खाद डालना आम बात है। बाढ़ की स्थिति में लगातार बनाए रखने के बजाय फसलों को बारी-बारी से सूखी और गीली स्थितियों के अधीन किया जाता है। यह तकनीक फसल के प्रतिरोध को बाढ़ और सूखे के लिए बढ़ा देती है, जबकि उत्पादन को 20% तक बढ़ा देती है और कम पानी का उपयोग करती है। यह तकनीक पौधों के बीच प्रतिस्पर्धा को कम करते हुए ऑक्सीजन की उपलब्धता में सुधार करती है।
- 2021 तक, आईआरआईआई, संयुक्त राष्ट्र और अन्य हितधारकों द्वारा समर्थित सस्टेनेबल राइस प्लेटफॉर्म- दुनिया भर में 1 मिलियन किसानों को स्थायी चावल की खेती के तरीकों पर स्विच करने के लिए राजी करना चाहता है।
- भारत में आधे से अधिक राज्य चावल की खेती करते हैं, जिससे यह देश के कृषि क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण घटक बन जाता है। यह कृषि समुदाय के एक महत्वपूर्ण वर्ग को उनकी आजीविका प्रदान करता है, और लोगों के एक बड़े हिस्से को उनके पोषण के साथ प्रदान करता है। नतीजतन, पानी और श्रम की कमी जैसी समस्याओं से फसल की रक्षा करना महत्वपूर्ण है। भारी जोखिमों को देखते हुए, चावल उत्पादन में पेश की गई किसी भी नई तकनीक को अत्यंत सावधानी के साथ किया जाना चाहिए। डीएसआर दृष्टिकोण तात्कालिक मुद्दों का समाधान है। वर्तमान क्षण एक अलग तरह की "हरित" क्रांति की मांग करता है, जिसमें इस बात पर जोर दिया गया है कि यह पर्यावरण और कृषि समुदाय को कैसे प्रभावित करेगी, जबकि 1950 और 1960 की हरित क्रांति ने खाद्य उत्पादन को बढ़ाने की मांग की थी।

Guru Deekshaa IAS is happy to announce first ever kannada current affairs magazine for kannada medium aspirants of Karnataka. The three important thumb rules for any competitive exam are



Vijay Kumar G

Founder and Director
Guru Deekshaa IAS

-  First-NCERT/STATE syllabus books which helps to develop your understanding on the subjects
-  Second-Daily current affairs helped to build your further understanding of the events related to your examination, Apart from knowledge it build the personality of an individual which brings in confidence to face any examination.
-  Third-Practice previous year question papers and mock test available in the market to train your mind as per the requirement of the examination.

Thousand miles of journey starts with single step, We at Guru Deekshaa have taken this first step towards empowering you to prepare for civil for services. Now its your turn to start preparation and achieve your dream of becoming IAS/IPS.

CALL US FOR MORE DETAILS

 **76 76 74 98 77**

JOIN OFFICIAL TELEGRAM FOR MATERIAL AND UPDATES

 @GURU_DEEKSHAAIAS



FOLLOW OUR INSTAGRAM FOR DAILY UPDATES

 GURUDEEKSHAA

